1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जून, 80	5.0	21.5	20.0	5.0	21.5	14.3	5.0	15.4	1.4
जुलाई, 80	10.0	21.5	20.0	10.0	21.5	7.8	1.8	10.4	0.4
अगस्त, 80	8.0	26.5	20.0	8.0	17.96	—	11.6	28.1	0.2
सितम्बर, 80	15.0	36.5	20.0	15.0	17.96	—	7.9	20.9	1.4
अक्तूबर, 80	15.0	36.5	20.0	15.0	14.5	—	4.5	15.9	2.4
नवम्बर, 80	15.0	36.5	20.0	15.0	14.5	20.0	2.4	10.6	0.5
दिसम्बर, 80	10.0	31.5	20.0	15.0	14.5	—	14.4	14.7	3.7
जनवरी, 1981	15.0	36.5	20.0	15.0	14.5	—	9.7	15.2	1.3

1. चावल और मोटे अनाज के लिए बताए गए आंकड़े सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हैं।

2. गेहूं के लिए बताए गये आंकड़े रोलर फ्लोर मिलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों के लिए हैं ।

मो० अ०—मोटे अनाज ।

नोएडा

2645. श्री केशव राव पारधी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोएडा द्वारा हुडको पद्धति के अन्तर्गत मध्यम श्रेणी के बने-बनाए फ्लैट देने के लिए 1979 में दिए गए एक विज्ञापन के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को छोड़कर) ने आवेदन-पत्र दिये;

(ख) इनमें कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने नियोक्ता का यह प्रमाण-पत्र संलग्न किया है कि यदि उसे मकान आवंटित कर दिया जाता है तो वह बाद में सारी राशि अर्थात् 46,200 रुपए नोएडा को सीधे

अदायगी कर देगा, ताकि उसे वही प्राथमिकता मिल सके जो नकद अदायगी करने वाले आवेदनकर्त्ताओं को दी जाती है ;

(ग) क्या नोएडा ने इन प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करने के बाद उन्हें वही प्राथमिकता दी जो कि नकद अदायगी करने वाले आवेदनकर्त्ताओं को दी जाती है, यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) तक. नोएडा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक विकास प्राधिकरण है। इसलिए यह सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Central Directive on Writing off Loans to Farmers

2646. SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY:
SHRI G. Y. KRISHNAN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Government has warned the States for writing off loans given by them to the farmers;

(b) if so, whether it has also been pointed out that if the practice continued, it would lead to total collapse of the agriculture credit system;

(c) if so, now many States have decided to write off the loans; and

(d) the total number of farmers benefited?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). Government of India are of the firm view that any measure involving blanket write-off of institutional loans tends to vitiate the climate for recovery encourage wilful default and undermine the viability of credit institutions. The framework for the Sixth Five-Year Plan and the Sixth Five-Year Plan approved by the National Development Council in August, 1980 and February, 1981, respectively, refer to the serious implications of write-off of institutional loans.

(c) and (d). The State Governments of Maharashtra and Tamil Nadu have decided to write off of institutional loans in their States covering 7.81 lakh small holders and 4.52 lakhs small farmers, respetcively. However. the actual number of farmers benefited will be known only after the amount to be written off is adjusted after scrutiny in the individual account of the borrower. Full details of the decision to write-off loans in other States are not available.

प्रत्येक खण्ड मुख्यालय के लिए टेलीफोन एक्सचेंज अथवा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा

2647. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की प्रत्येक खंड मुख्यालय में एक टेलीफोन एक्सचेंज अथवा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) छठी योजना में प्राथमिकता के आधार पर बाकी के कितने स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) 97 प्रतिशत से ऊपर ।